an>

Title: Need to set up Kisan Counselling Centres.

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली)ः मैं सरकार का ध्यान 'देश में किसानों की स्थिति' पर दिलाना चाहता हूं। हमारे देश की 70 फीसदी आबादी गाँवों में रहती है और कृषि पर ही निर्भर हैं। ऐसे में किसानों की खुशहाली की बात करते हैं और उनके लिए योजनाएं भी बनाते हैं किन्तु उनकी मूलभूत समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है और इसका कारण सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और किसानों के बीच की कड़ी का न होना है।

स्वतंत्र भारत से पूर्व और स्वतंत्र भारत के पश्चात एक लंबी अवधि व्यतीत होने के बाद भी भारतीय किसानों की दशा में वांछित सुधार नहीं हुआ है। जिन अच्छे किसानों की बात की जाती है उनकी गिनती उंगलियों पर की जा सकती है और आज आजादी के 68 सालों बाद भी हमारे किसान भाइयों को लेनदारों का सहारा लेना पड़ता है।

केन्द्र सरकार ने इस बार के बजट 2016-17 में किसानों, मजदूरों एवं गरीब परिवारों को ध्यान में रखते हुए कृषि और किसान कल्याण के लिए कुल आवंटन 35,984 करोड़ रूपये दिये हैं, जो कि सिंचाई के लिए नई अवसंरचना निर्मित करने, उर्वरकों का संतुलित प्रयोग, मृदा की उर्वरकता बनाए रखना, मूल्यवर्धन प्रदान करना एवं खेत से बाजार तक संपर्क बनाना इत्यादि है। हमारी सरकार ने देश के इतिहास में पहली बार किसानों के लिए फसल बीमा योजना की शुरूआत की है जिसका एकमात्र ध्येय किसानों की मूलभूत समस्या को दूर करने का एक प्रयास है। समस्या यह है कि ज्यादा पढ़े-लिखे ना होने के कारण हमारे किसान भाई इन सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पाते , जिसके कारण उन्हे बाद में भारी हानि का सामना करना पड़ता है जो फसल की बर्बादी से लेकर लेनदारों द्वारा लिए गए कर्ज तक होती है। इन सबसे न सिर्फ एक किसान अपितु एक परिवार को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारी सरकार देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में **'किसान काउंसलिंग सेन्टर'** खोले, जहां किसान भाइयों को खेती से संबंधित सुविधा एवं जानकारी यथा-बैंक से कर्ज का लाभ उठाना, फसलों का समय पर बीमा करवाना जैसे जानकारी उन्हें समय रहते दी जा सके। जिससे जो समय-समय पर केन्द्र और राज्य सरकारें किसानों को ऋण मुक्त करने के लिए ऋण माफी की अनेक योजनाएं घोषित करती है और जिसकी जानकारी के अभाव में वे इससे लाभान्वित नहीं हो पाते, उनका उन्हें लाभ मिल सके। केवल जानकारी के अभाव में हमारे किसान भाइयों को आस-पास के लेनदारों से कर्ज लेने पड़ते हैं, जो बाद में उनके लिए बोझ बन जाता है। जितनी जरूरत किसानों को सरकार की योजनाओं की है उससे ज्यादा जरूरत उन्हें 'किसान काउंसलिंग सेन्टर' की है ताकि समय रहते वो इन योजनाओं का लाभ उठाने में सक्षम हों और उन्हें हम भारत की प्रगति की मुख्य धारा से जोड़ने में सफल हो सकें।

मेरा सरकार से विनम्र निवेदन है कि किसानों के लिए 'काउंसलिंग सेन्टर्स'की व्यवस्था कराये।